(d) Based on documented latest figures (1992-93) expenditure on Agricultural Research, Education and Extension Education by ICAR/DARE, it is 0.186 per cent. This does not include expenditure by the State Government on the State Agricultural Universities and other research units operated by them. Since agriculture is a State subject, such expenditures are quite significant.

Schemes by U.P. Agricultural Development

4893. SHRI SANJAY DALMIA:

MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the State Government of Uttar Pradesh have submitted some schemes relating to agricultural developments to the Central Government for approval;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the decision taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (c) The Government of Uttar Pradesh has submitted a proposal for inclusion of a project. Uttar Pradesh Diversified Agriculture Support Project for World Bank Assistance. The Government of Uttar Pradesh is already engaged in conducting studies for different components under this Projet. The project preparation is still in the initial stages.

The Government of Uttar Pradesh has also forwarded a project proposal for Training and Extension of Women in Agriculture to be funded by the Government of Netherlands. The Project has been returned to U.P. Government for certain clarifications.

"गोपाल योजना" का कार्यान्वयन

4894. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जहां पशुधन की नस्ल के समेकित विकास हेतु "गोपाल योजना" को लागू किया जा रहा है ;

(ख) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत किए गए उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपर्युक्त योजना को लागू करने के लिए राज्य-वार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) "गोपाल योजना" के नाम से कोई योजना नहीं है। तथापि, वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना को क्रियान्वित करने वाले राज्यों को, चुनिन्दा पनधारा के प्रत्येक गांव में जो परियोजना के पशुधन विकास घटक से भी सहयोजित है, एक भूमिहीन सम्पर्क किसान को "गोपाल" नाम से पदनामित किए जाने की आवश्यकता है । उन राज्यों के नाम जो वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना को क्रियान्वित कर रहे हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं । (नीचे देखिए) ।

(ख) इस योजना के अंतर्गत किए गए उपायों में परियोजना क्षेत्रों में विनियमित प्रजनन तथा नस्ल सुधार को सुसहाय बनाने के लिए मुख्य रूप से निकम्मे सांडों का बधियाकरण करना है । परियोजना क्षेत्रों के प्रत्येक गांव से कम से कम एक शिक्षित भूमिहीन कृषि श्रमिक का सम्पर्क कृषक के रूप में चयन किय जाता है जिसे "गोपाल" के नाम से जाना जाता है । गोपाल तथा अन्य ग्रामीण युवक जिन्हें बधियाकरण में रूचि है, उन्हें एक स्व-सहायता दल में संगठित किया गया है, जिसमें चार या पांच व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं । ऐसे स्व-सहायता दलों को बधियाकरण में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इसके पश्चात उच्च कोटि के बधियाकर्ताओं की सेवाएं स्व-सहायता दलों को प्रदान की जाती हैं जो परियोजना/क्षेत्रों में भुगतान के आधार पर बधियाकरण करते हैं ।

(ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	प्रशिक्षित गोपालों की संख्या (प्रारंभ से मार्च 1995 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,347
2.	असम	1,439
3.	बिहार	101
4.	गुजरात	1,838
5.	हरियाणा	162
6.	हिमाचल प्रदेश	699
7.	जम्मू और कश्मीर	295
8.	कर्नाटक	1,434
9.	केरल	6,629
10.	मध्य प्रदेश	11,158
11.	महाराष्ट्र	4,938
12.	मणिपुर	133
13.	मेघालय	16
14.	नागालैण्ड	46
15.	उड़ीसा	1,135
16.	पंजाब	269
17.	राजस्थान	2,254
18.	तमिलनाडु	7,490
19.	त्रिपुरा	94
20.	उत्तर प्रदेश	789
21.	पश्चिम बंगाल	507
22.	सिक्किम	2,053
23.	गोवा	0
24.	अरुणाचल प्रदेश	18
25.	मिजोरम	128
	कुल:	46,972